संपादकीय

बीमा कंपनियों व अस्पतालों का मकड़जाल

बीमा कारोबार की जटिलताएं हमेशा से ही आमजन के लिए एक अनसुलझी गुत्थी रही हैं। हमारी भविष्य की आशंकाओं व भय पर फल-फूल रहे इस कारोबार को लेकर गाहे-बगाहे परेशान करने वाली खबरें आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद तेजी से फल-फूल रहे विभिन्न बीमा कारोबारों की विसंगतियां कम नहीं हुई हैं। इसी तरह मेडिकल बीमा को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आती रही हैं। दरअसल, लगातार महंगी होती चिकित्सा सुविधाओं के दौर में, भविष्य में महंगे इलाज का खर्च उठाने का भरोसा दिलाकर बीमा कंपनियां लोगों को बीमा पॉलिसियां खरीदने को मानसिक रूप से तैयार कर लेती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब वास्तव में कोई बीमार पड़ता है तो इलाज पर हुए खर्च के भुगतान को लेकर तमाम किंतु-परंतु बीमा कंपनियां करने लगती हैं। कई खामियां निकाली जाती हैं, जिनके बारे में बीमा धारक को पता ही नहीं होता है। कई बार तो छिपे-ढके कारण बताकर चिकित्सा खर्च की भरपाई करने से भी मना कर दिया जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीए के आंकड़ों ने बीमा कंपनियों के मुनाफा खेल को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में छब्बीस हजार करोड़ रुपये के बीमा दावे खारिज किए गए थे। निःसंदेह, ये आंकड़ा बीमा कंपनियों तथा पांच सितारा अस्पताल प्रबंधकों के अपवित्र गठबंधन को ही दर्शाता है। बाकायदा पिछले दिनों राज्यसभा में निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के अपवित्र गठजोड़ का मामला उठाया गया। जो हर साल हजारों लोगों को कर्ज व गरीबी की दलदल में धकेल देता है। अक्सर आरोप लगता है कि मरीजों को उपचार के मुकाबले बेहद कम राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों व बीमा कंपनियों के मध्य सांठगांठ के मामले सामने नहीं आते। लेकिन हमारा नियामक-तंत्र सारे घटना म की अनदेखी कर देता है। विडंबना यह भी है कि केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर भी इस मुनाफाखोरी पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया जाता है, जिससे लोगों को उलटे उस्तरे से मूंडने का खेल बदस्तूर जारी रहता है। दरअसल, लोग जब कोई स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो उन बारीकियों के बारे में नहीं बताया जाता है, जिसके आधार पर मरीजों के चिकित्सा बीमा राशि को खारिज किया जाता है। अक्सर इलाज के बड़े खर्चे के दावे को कई मीन-मेख निकालकर नकार दिया जाता है। कई बार तो अमानवीयता की हदें भी सामने आती हैं जब मरीज की मृत्यु पर, खर्च चुकाने में असमर्थ होने पर अस्पताल प्रबंधक परिजनों को पार्थिव शरीर तक को देने से मना कर देते हैं।

विनोद शर्मा, संपादक

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था

शहर बर्बाद होते हैं, अर्थव्यवस्था टूटती है और आने वाली पीढ़ियां तक उसके दुष्परिणाम झेलती हैं। इसलिए आज दुनिया को हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की दौड़ की जरूरत है। हथियारों की होड़ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ा रही हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा हिस्सा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए तो दुनिया से गरीबी और भूख को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया की राजनीति अभी भी शक्ति संतुलन और सैन्य प्रभुत्व के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व नेतृत्व यह समझे कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास में होती है। जो देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली देश होता है।

ललित गर्ग

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था आज मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर खड़ी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े जाने वाले संघर्ष नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, पर्यावरण, सृष्टि-संतुलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान और इजरायल के बीच हमलों का नया दौर, अमेरिका की रणनीतिक भूमिका, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान तनाव जैसे अनेक घटनाक्रम मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ और शक्ति संतुलन की राजनीति की ओर लौट रही है। यह स्थिति केवल राजनीतिक या सामरिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट का संकेत भी है, क्योंकि जब दुनिया हथियारों पर ज्यादा खर्च करती है तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं। आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना यह है कि जितने अधिक हथियार बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी ही असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में असुरक्षा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविश्वास का वातावरण बन जाता है। यह अविश्वास ही युद्ध की जमीन तैयार करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और यह पैसा मानव विकास के बजाय विनाश की तैयारी में खर्च होगा। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए शुभ संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हमले, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव और बड़े देशों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी ने इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समुद्री मार्ग खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इजरायल पर हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिससे यह संकट और अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर है और पश्चिम एशिया तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि वहां युद्ध बढ़ता है या समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और अंततः हर वस्तु महंगी हो जाएगी। यानी एक वैश्विक महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी जा सकती है। पहले से ही कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और यदि ऊर्जा संकट बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। भारत जैसे देश भी इस स्थिति से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। केवल केंद्र सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं होगी, राज्य सरकारों को भी इस स्थिति को समझते हुए ऊर्जा संरक्षण, आपूर्ति प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया युद्ध को रोकने के बजाय उसकी तैयारी ज्यादा कर रही है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन होता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध ऐसे हुए जो कुछ दिनों के लिए शुरू हुए लेकिन वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी यदि पश्चिम एशिया का युद्ध फैलता है तो यह केवल दो या तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की भागीदारी से यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि विश्व के बड़े देश आगे बढ़कर युद्ध विराम की पहल करें और वार्ता का रास्ता निकालें। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहे तो वह इजरायल पर दबाव डाल सकता है, ईरान के साथ वार्ता शुरू करा सकता है और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से युद्ध विराम की दिशा में कदम उठा सकता है। कूटनीति का रास्ता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध में अंततः नुकसान सभी का होता है। युद्ध में सैनिक मरते हैं, नागरिक मरते हैं।

धर्म और जाति को लेकर आए सुप्रीम आदेश के राजनीतिक-सामाजिक मायने

कमलेश पांडे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। दरअसल, आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई पादरी से जुड़े मामले में आए इस नवीनतम फैसले के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। इससे हिन्दू समुदाय के दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर धर्मांतरित करवाये जाने का पूरा खेल ही अब हतोत्साहित हो जाएगा। हालांकि, कांग्रेस व समाजवादी मूल की क्षेत्रीय पार्टियां यदि चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती है कि जब हिन्दू, बौद्ध या सिख बनेंगे तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन है, जो हर गतिरोध के बाद एक नया गतिरोध पैदा कर देता है। कहने का तातपर्य यह कि ज्यूडिशियल एंटीबायोटिक पॉवर बढ़ाये बिना सम्बन्धित व्यक्ति या समूह का कल्याण नहीं होने वाला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 23-24 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई, इस्लाम आदि) में परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। इस आदेश से एससी/एसटी आरक्षण लाभ और अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण खत्म हो जाता है। दरअसल, यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के आदेश पर आधारित है, जहां एक ईसाई पादरी को एससी/एसटी एक्ट के तहत संरक्षण से वंचित किया गया। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल निर्दिष्ट धर्मों के अनुयायी ही एससी लाभ ले सकते हैं। ईसाई या इस्लाम अपनाने पर जातिगत पहचान और लाभ दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस फैसले के अहम राजनीतिक मायने हैं। यह फैसला धर्मांतरण पर आधारित आरक्षण दावों को रोक सकता है, जो दक्षिणपंथी दलों के लिए समर्थन बढ़ाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक आरक्षण बहस (जैसे दलित ईसाई/मुस्लिम) को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में हिंदू एकता पर जोर देगा। राज्य सरकारें ओबीसी/एससी सूचियों की समीक्षा के दबाव में आ सकती हैं। वहीं, इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़ी बहस जोर पकड़ सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में फैसला दिया है, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते है जहां कानून और जमीनी हकीकत आमने-सामने आ जाते हैं। भारत में जाति एक सच्चाई है, जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी बुराइयों को खत्म करने की तमाम कोशिश होनी चाहिए। जो राजनीतिक और न्यायिक अदूरदर्शिता वश नहीं हो पा रही है और तरह तरह के संवैधानिक विवाद जन्म ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को लगातार धक्का लग रहा है। जहां तक इस फैसले के सामाजिक प्रभाव की बात है तो धर्म परिवर्तन के बाद एससी/ओबीसी का लाभ न मिलने से सामाजिक न्याय की नीति मजबूत होगी, लेकिन धार्मिक रूपांतरण रोकने या जातिगत अस्मिता पर बहस तेज हो सकती है। चूंकि दलित समुदायों में हिंदू/सिख/बौद्ध रहने का दबाव बढ़ेगा, जबकि ईसाई/मुस्लिम समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। इस पर मौजूदा मोदी सरकार के वैचारिक असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार दलित/ओबीसी हिंदुओं की एकजुटता व समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि देश में जाति से जुड़ा सवाल बहुत टेढ़ा और जटिल है। क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि क्या धर्म बदलने भर से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? गाहे बगाहे ऐसे मामले सामने आते रहे है, जिनमें दलित या ओबीसी समुदाय के लोगों को दूसरा धर्म अपनाने के बाद भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिछले साल मार्च में ही तमिलनाडु के कुछ ईसाई परिवारों, जो पहले दलित थे, ने आरोप लगाया था कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। यहां तक कि कब्रिस्तान में उनके लोगों के शवों को दफनाने के लिए भी अलग जगह है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के फैसले का आधार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 है। जिसका क्लॉज 3 कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही एससी श्रेणी में आ सकते है। धर्म परिवर्तन और जाति से जुड़ी यह बहस बहुत पुरानी है। इसके दो पहलू है। एक, जिन धर्मों में जाति व्यवस्था नही है, उन्हें अपनाकर फिर जाति से जुड़े लाभ कैसे लिए जा सकते है।

खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

सांसद बनने के बाद खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पूरी सक्रियता के साथ लोकसभा क्षेत्र के विकास एवं क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान करने को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। लोकसभा सत्र के दौरान अपने क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं को लेकर पूरी ताकत के साथ लोकसभा पटल पर अपनी बात रखते हुए कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि चल रही लोकसभा सत्र के दौरान सांसद श्री पाटिल ने लोकसभा में न्यायालय के कार्यों में हिंदी एवं ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में अनाज वितरण की समस्या को लेकर अपनी बात रखी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मंगलवार शाम को रेल भवन पहुंच कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर विभिन्न रेल मुद्दे उठाएं। इस मौके पर सांसद पाटिल के साथ खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल मौजूद थे। प्रवक्ता सुनील जैन,मध्य रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर खंडवा संसदीय क्षेत्र से जुड़े रेल मुद्दों को उठाया और उन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कोरोना काल से बंद की गई नागपुर भुसावल ट्रेन को पुनः शुरू करने की बात पुरजोर तरीके से रेल मंत्री के समक्ष रखी। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक जवाब दिया है रेल मंत्री वैष्णव ने कहा नागपुर भुसावल ट्रेन जल्द पुनः शुरू की करेंगे। सांसद पाटिल ने ओंकारेश्वर स्टेशन का कार्य अंतिम चरण में होने की बात कही है तथा रेल मंत्री की मौजूदगी में इसका लोकार्पण करने का अनुरोध किया।रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ लोकार्पण की संभावना जताई। सांसद पाटिल ने खंडवा स्टेशन री डेवलपमेंट में सेंट्रल रेलवे द्वारा अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर चिंता जताई । रेल मंत्री ने संबंधित अधिकारी बुला कर को इस विषय पर कार्रवाई के लिए कहा। खंडवा स्थित लाल चौकी रेल फाटक पर प्रतिदिन जाम से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी से अवगत कराया इसका समाधान करने की बात कही। रेल मंत्री ने वहां उपस्थिति अधिकारी से इस पर कार्रवाई को कहा। साथ ही खंडवा आमलाखुर्द के बीच 2 वर्ष पूर्व सीआरएस होने बाद भी अभी तक आमजनता को कोई यात्री ट्रेन सुविधा नहीं मिलने बात कही इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सकारात्मक जवाब दिया है । प्रवक्ता सुनील जैन रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि इस मुलाकात में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर और खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने खंडवा अलीराजपुर नये रेलमार्ग को स्वीकृत करने की मांग रखी।

लायन्स क्लब खण्डवा ने ग्रीष्मकालीन प्याऊओ का किया शुभारंभ

सोडानी व मोदी ने लायन्स भोजन सेवा केंद्र का किया अवलोकन

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

लायन्स क्लब खण्डवा एवं लियो क्लब खण्डवा द्वारा सेवा कार्यों की श्रृंखला में ग्रीष्मकालीन जल सेवा का शुभारंभ करते हुए शहर में विभिन्न स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए जा रहे हैं। क्लब द्वारा वर्षों से स्थायी प्याऊ के साथ-साथ ग्रीष्मकाल में अस्थायी प्याऊ लगाकर राहगीरों, मरीजों एवं जरूरतमंदों को शीतल जल उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नारायण बाहेती ने बताया कि क्लब अध्यक्ष लायन आशा उपाध्याय, उपाध्यक्ष लायन घनश्याम वाधवा, सचिव लायन ओमप्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन पवन लाड़, लियो क्लब अध्यक्ष लियो सुमित परिहार, सचिव लियो अभिषु शर्मा एवं कोषाध्यक्ष लियो केतन वर्मा व अपूर्व उपाध्याय के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय परिसर स्थित ग्रीष्मकालीन प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लायन्स डिस्ट्रिक्ट के वरिष्ठ लायन डॉ. राजेन्द्र सोडानी एवं लायन अनिल मोदी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने करकमलों से प्याऊ का उद्घाटन किया। क्लब द्वारा नगर निगम के सहयोग से शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी शीघ्र ही प्याऊ प्रारंभ किए जाएंगे। अतिथियों ने लायन्स क्लब खण्डवा द्वारा संचालित लायन्स भोजन सेवा केंद्र का अवलोकन भी किया तथा स्वयं अपने हाथों से मरीजों, उनके परिजनों एवं जरूरतमंदों को भोजन परोसा। इस दौरान गांधी प्रसाद गदले, नारायण बाहेती, राजीव शर्मा, गुरमित सिंह उबेजा, राजीव मालवीय एवं अखिलेश गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सेवा केंद्र की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डॉ. राजेन्द्र सोडानी ने कहा कि लायन्स क्लब खण्डवा द्वारा संचालित भोजन सेवा केंद्र ने न केवल लायन्स प्रांत बल्कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस दिशा में क्लब की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। वहीं लायन अनिल मोदी ने कहा कि लायन्स क्लब खण्डवा सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है। क्लब की आपसी फेलोशिप एवं वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन इसकी सफलता का प्रमुख आधार है। सेवा के इस कार्य की लायंस क्लब को शुभकामना देते हुए समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि परम श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज अपनी हर कथाओं में रहते थे कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस उपदेश को लेकर लायंस और लियो क्लब जगह-जगह पर इस भीषण गर्मी में लोगों को जल से तृप्त करने के लिए ठंडे पानी के प्याऊ लगा रहा है एक पुण्यशाली अच्छा कदम है। इस अवसर पर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रणवीर सिंह चावला, बी.पी. तिरोले, बी.आर. तिरोले, रेखा रामस्नेही, सनत श्रीमाली, राजू जोशी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, समाजसेवी सुनील जैन, हरजीत सिंघ खरबंदा, गुरजीत सिंघ चावला, अविनाश शुक्ला, संजय गंगराड़े सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।

ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रियों के लिए श्री कृष्ण बालाजी नगर रुकने के लिए एक शानदार केंद्र होगा

केवल घर बेचना हमारा उपदेश नहीं, परिवार में खुशी और अच्छा माहौल देना हमारा उपदेश हैः रितेश गोयल

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

बड़े शहरों की तर्ज पर दादाजी की नगरी खंडवा में चारों दिशाओं में बालाजी ग्रुप के हितेश गोयल परिवार द्वारा शानदार आधुनिक कॉलोनीयो का निर्माण किया गया है बड़ी संख्या में और वासी बालाजी ग्रुप की कॉलोनी में अपना आशियाना बना रहे हैं। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि खंडवा के साथ ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप श्री कृष्ण बालाजी नगर का निर्माण किया जा रहा है जहां भगवान केदारनाथ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। एवं ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अच्छी सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध होगी। श्री कृष्णा बालाजी नगर में निवेश का सुनहरा अवसर हें,अब हॉलिडे होम होंगे व्यवसाय का माध्यम, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अब ठहरने का अनुभव बदलने वाला है। सनावद में, ओंकारेश्वर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर बालाजी ग्रुप द्वारा एक अनूठी कॉलोनी श्री कृष्ण बालाजी नगर की शुरुआत की गई है। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की हॉलिडे होम प्लानिंग है, जो निवेश के साथ-साथ शानदार रिटर्न की गारंटी भी देती है।

क्या है हॉलिडे होम कॉन्सेप्ट: इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निवेशक अपना निजी हॉलिडे होम खरीद सकते हैं। इसका दोहरा लाभ यह है कि जब भी उनके मेहमान ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आएं।

झमराल समाज ने 62 वे वर्ष में हर्षोल्लास से मनाया गणगौर उत्सव

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा।

झमराल समाज खण्डवा का 62 वा वर्ष इस साल में पूर्ण हुआ है यहां प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणगौर उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया गया। विधि विधान से माता की पूजा पाठ की गई। झमराल चौक में माताजी के रथ को दूसरे दिन रोका गया एवं तींसरे दिन माताजी का भंडारा करके विसर्जन किया गया।समाजसेवी नारायण बाहेती व सुनील जैन ने बताया कि इस आयोजन में विधायक श्रीमती कंचन तनवे, महापौर श्रीमती,अमृता यादव सहित जन प्रतिनिधियों ने भी उपस्थिति दर्ज कर माता जी के गणगौर पर्व की समाजजनों को शुभकामनाएं दी ।महापौर अमृता अमर यादव ने गणगौर पर्व के बारे में जानकारी दी। इस उत्सव में आम जनमानस के साथ-साथ समाज के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। देवेंद्र डांडगे, बाबूलाल बिढारे, ललित ढास्के, कमल बिढारे, राजेश ढास्के, प्रवीण ढास्के, मोहन डांडगे,बिरजू जामने,रविन्द्र बिढारे , अनिल बिढारे, आदित्य ढास्के, अंकलेश बिढारे, महेंद्र सावले, ज्ञानेश्वर डांडगे, सुरेंद्र बिढारे, प्रदीप बिढारे, देवेंद्र बिढारे, हेमू बछाने,मोंटी जामने, नितेश बछाने शामिल रहे।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059